DETAILS OF RESEARCH PAPER :-

Dr.ARADHANA SHUKLA:-

(Department of Commerce)

S.N.	Title of paper	Name of journal	Year of publication	ISSN NO.
01.	BHARAT KE AARTHIK VIKAS ME VIDESHI PUNJI EVAM SAHYOGKI BHUMIKA	Naveen Shodh Sansar	2015	2394-3793
02.	RAIPUR KSHETRA KE ASANGHATITH KSHETRA ME BAL SHRAMIK KE MAJDURI KA AARTHIK ADHHAYAN	IJASS	2016	2454-2679
03.	BHARAT KI GARIBI NIVARAN YOJANAO KA MULYAKAN	Naveen Shodh sansar	2017	2394-3793
04.	CHHATTISHGARH NAGAR PALIK NIGAMO KE DWARA PRADAN KIYE GAYE SUVIDHAO KA VISHALESHANATAMAK ADDHYAN	IJASS	2018	2347-5153
05.	KARYASHIL PUNJI DIVAS KI AVDHARNA	IJRRSS	2018	2347-5145
06.	CHHATTISGARH KE NAGAR -PALIK NIGAMO KE BAJATIY ISTHITI KA VISHLESHAN	IJRSS	2018	2347-5145
07.	ANTARASHTRIYA MUDRA KOSH EVAM BHARAT	Naveen Shodh sansar	2018	2394-3793

Edit with WPS Office

08	CONTRIBUTION OF INDUSTRIAL SECTOR'S IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN INDIA	JOURNAL ADVANCES &SCHOLARY RESEARCHES IN ALLIED	2018	2230-7540
09.	SKILL DEVELOPMENT PROGRAMME & SELF-EMPLOYMENT OPPORTUITY IN CHHATTISHGARH	DIVYA SHODH SAMIKSHA	2019	2394-3513

Edit with WPS Office

Volume I, E - Journal
Jan. to March 2015

Reg. No. MPHIN/28519/12/1/2012-TC
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 0.715 (2014)

Naveen Shodh Sansar

(An International Multidisciplinary Refereed Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

Edit with WPS Office

28. The Best Approach To Environmental Management Is An Integrated Approach For Environment Problem & its Effect (Dr. Kanti Pachori) 68

29. Symbolism in the poetry of W.B. Yeats (Dr. Pratibha Rajpoot) 72

30. भारत और वैश्वीकरण – सामाजिक और राजनीतिक सन्दर्भ (डॉ.उमेद प्रसाद विश्वकर्मा) 74

31. मनुष्य के जीवन मे जैव विविधता का महत्व (डॉ. दयाराम साहू) 78

32. आर्थिक विकास में कृषि जैव विविधता का महत्व (डॉ. दयाराम साहू) 81

33. कोल इण्डिया लिमिटेड में प्रशिक्षण की भूमिका (डॉ. दीपचंद भावंरकर) 85

34. कार्यस्थल पर अच्छे वातावरण का महत्व कोल इण्डिया लिमिटेड के संदर्भ में (डॉ. दीपचंद भावंरकर) 87

35. जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावों का मूल्यांकन (विश्लेषणात्मक अध्ययन) (डॉ. राजेश कुमार लोखण्डे) 89

36. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ और कमियाँ (डॉ. राजेश कुमार लोखण्डे) 92

37. प्रसिद्ध कहानियों पर बनी हिन्दी फिल्मों का आकलन (डॉ. मजीद कुरैषी) 94

38. सामाजिक चेतना के कारकों के निर्धारण में वैश्वीकरण का प्रभाव (डॉ.उमेद प्रसाद विश्वकर्मा) 99

39. छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीतियों का जनजातियों पर प्रभाव – एक अध्ययन (जैनेन्द्र कुमार पटेल) 104

40. Agonies of the times author lived in and the subsequent manifestation of violence in the novels of Ernest Hemingway (Haroon Bashir Kar) 106

41. Human Resource Information System:An Innovative Strategy for Human Resource Management (Dr. Aalok Kumar Yadav) 108

42. महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा की अवधारणा का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य (डॉ. बी. के. गुप्ता) 111

43. गैरतगंज ब्लाक में कृषि का निदानात्मक अध्ययन (रत्नेश नारायण श्रीवास्तव) 113

44. Stress Management (Dr. Anita Dani) 115

45. भारत के आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी एवं सहयोग की भूमिका (डॉ. आराधना शुक्ला, निधि श्री) 117

Edit with WPS Office

भारत के आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी एवं सहयोग की भूमिका

डॉ. आराधना शुक्ला* निधि श्री**

शोध सारांश – भारत में निवेश के लिए विदेशी व्यक्तियों अथवा कंपनियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये पूंजी को विदेशी पूंजी कहते है, विदेशी पूंजी शब्द एक व्यापक शब्द हैं, जिसके अंतर्गत , 1. विदेशी सहायता , 2. व्यापारिक ऋण , 3. विदेशी निवेश को सम्मिलित किया जाता है। किसी देश की उत्पादक क्रियाओं में विदेशी सरकार, विदेशी निजी व्यक्ति व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किए गए पूंजी निवेश (विनियोग) को विदेशी पूंजी कहते हैं। किसी भी विकासशील देश के विकासात्मक परियोजनाओं की सफलता विदेशों से प्राप्त अनुदान एवं प्राप्त रियायती ऋणों पर निर्भर करता है क्योंकि इन योजनाओं के लिए विशाल मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसे आसानी से विदेशी सहायता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, विदेशों से प्राप्त अनुदान को वापस नहीं करना होता है , तथा रियायती ऋणों पर ब्याज की दर काफी कम होती है, और इसे वापस करने की अवधि बहुत लम्बी होती है। इस शोध पत्र में यह अध्ययन करने का प्रयास किया गया है कि विदेशी पूंजी का भारत के आर्थिक विकास में किस प्रकार अहम् भूमिका रही।

शब्द कुंजी – विदेशी सहायता, आर्थिक सहायता।

प्रस्तावना – भारत एक विकासशील देश है, जिसके आर्थिक विकास हेतु आधारभूत संरचना योजनागत व्ययों के लिए वृहत निवेश की आवश्यकता है, जिसे भारतीय निजी एवं सरकारी निवेश के द्वारा पूर्ति नहीं किया जा सकता, इस हेतु विदेशी सहायता की आवश्यकता होती है, विदेशी पूंजी के द्वारा भारत के आर्थिक विकास हेतु आवश्यक विशाल पूंजी की व्यवस्था की जा सकती है, सामान्यतया विदेशी व्यक्तियों एवं कंपनियों के द्वारा आवश्यक पूंजी को उपलब्ध कराना ही विदेशी पूंजी कहलाता है, जो विदेशी सहायता, विदेशी निवेश या व्यापारी के रूप में हो सकती है।

विदेशी सहायता – विदेशी पूंजी का वह रूप है, जो विकसित देशों की सरकारों, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विकासशील देशों के आर्थिक विकास की दर को तीव्र गति प्रदान करने के लिए उपलब्ध करायी जाती है।

व्यापारिक ऋण – जब विदेशी सहायता से प्राप्त राशि किसी देश के विकासात्मक योजनाओं को गति प्रदान करने में अपूर्ण होती है तो ,विदेशी बैंकों से बाजार में प्रचलित ब्याज दर पर ऋण लिए जाते है, साथ ही साथ भारत के बैंकों में अनिवासी भारतीयों के जमा राशि को विकासात्मक योजनाओं में प्रयोग किया जाता है, जिसे व्यापारिक ऋण कहते हैं। उक्त दोनों विदेशी पूंजी योजनागत परियोजनाओं हेतु वांछित व्यय की राशि को पूर्ण नहीं कर पाते हो तो, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग जिसके अंतर्गत विदेशी नागरिक अथवा संगठन दूसरे देश में अपनी पूंजी द्वारा उत्पादन इकाई स्थापित करता है या फिर विदेशी कंपनीयां , पोर्ट फोलियो निवेश के द्वारा भारतीय कंपनियों के अंश खरीदकर विनियोग करती है, इस प्रकार ये दोनों ही रास्ते **विदेशी विनियोग** माने जाते है, भारत जैसे विकासशील देशों में जहां आर्थिक विकास हेतु आवश्यक पूंजी एवं आधुनिक तकनीकी का अभाव है, वहां पर तकनीकी पूंजी संजीवनी का कार्य करती है। भारत ने नयें आर्थिक सुधारों के लिए विदेशी पूंजी कारगर सिद्ध हुई है, 1991 में आर्थिक सुधारों के पश्चात् भारत में विदेशी तकनीकी सहयोग तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में निरंतर वृद्धि हुई है। जुलाई–अगस्त, 1991 में घोषित उदार विदेशी नीति के परिणामस्वरूप, विदेशी सहयोग के समझौतों में तथा विदेशी निवेश में तेज वृद्धि हुई है। **क्षेत्रानुसार में विदेशी तकनीकी स्थानांतर सहयोग अनुमोदित**, 1991 से अगस्त, 2011 के बीच सर्वाधिक तकनीकी सहयोग का अनुमोदित बिजली उपकरण (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सहित) को 15 प्रतिशत हुआ था, उसके बाद क्रमशः रसायन (11.20%), औद्योगिक मशीनरी (10.79%), परिवहन उद्योग (9.36%), विविध इंजीनियरिंग उद्योग 5.50% किया था। भारत सरकार ने विदेशी सहयोगों को बढ़ावा देने के लिये कई प्रयास किये हैं। इसके लिये कुछ क्षेत्रों में 100 प्रतिशत विदेशी क्षमता निवेश की सहमती दे दी गयी , तथा विदेशी पूंजी के फलस्वरूप हमारा राष्ट्रीय आय का 5 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1989–90 में 22 प्रतिशत और 2007–08 में 33 प्रतिशत हो गयी। 1970 के दशक से ही देश को विदेशी मुद्रा के संकट का सामना करना पड़ता है, इस संकट को दूर करने और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में विदेशी सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विदेशी पूंजी व सहयोग ने देश में भारी व आधारभूत उद्योगों की स्थापना, परिवहन, संचार व विद्युत उत्पादन का विस्तार करके जहाँ एक ओर देश में औद्योगीकरण के लिए आधारभूत संरचना का विकास किया हैं, वहीं दूसरी ओर देश के महत्वपूर्ण उद्योगों में विदेशी पूंजी विनियोग के द्वारा औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका हैं। देश को विदेशी पूंजी के अन्तर्गत विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं, भारतीयों को प्रशिक्षण की व्यवस्था और तकनीकी परामर्श के साथ साथ अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन मिला है।

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) गुरूकुल महिला महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत
** शोधार्थी,पं. रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

परिवहन व संचार के साधनों के विकास में विदेशी पूंजी का सहयोग होता है। कुल विदेशी पूंजी का 14 प्रतिशत भाग परिवहन व संचार के विकास पर व्यय किया गया है। इनमें से 12 प्रतिशत व्यय रेल परिवहन के विकास पर हुआ। किसी भी देश के आर्थिक विकास में लोहा व इस्पात उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्वतन्त्रता–प्राप्ति के समय भारत में यह उद्योग अविकसित अवस्था में था, किंतु आज हम लोहे का निर्यात कर रहे हैं। निर्माण उद्योगों के लिए किया गया है पश्चिमी जर्मनी , रूस तथा ब्रिटेन ने इस उद्योग को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

विश्लेषण – भारत में विगत वर्षों में विदेशी निवेश की प्रवृत्ति निम्न है :

	2010 –11	2011 –12	2012 –13	2013 –14	2014 –15
विदेशी निवेश :	42,127	39,231	46,710	26,386	38,385
(क) एस.डी. आई	11,834	22,061	19,819	21,564	16,183
(ख) पोर्ट फोलिया निवेश :	30,293	17,170	26,891	4,822	22,202

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि बढ़ता हुआ विदेशी निवेश भारत के बहुमुखी आर्थिक विकास हेतु संजीवनी का कार्य कर रहा है। भारत के आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी निवेश ने भारी उद्योगों की स्थापना की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है तथा खाद्य संकट हल करने, सिंचाई एवं बिजली क्षमता का विस्तार करने, रेलवे का विकास करने, तकनीकी विकास एवं प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त करने में काफी सहयोग दिया है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत के आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी एवं सहयोग की भूमिका निभा रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. एस.के.सिंह , व्यावसायिक पर्यावरण , साहित्य भवन पब्लिकेशन्स
2. डॉ. मिश्र एवं शुक्ल, व्यावसायिक पर्यावरण, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स
3. डॉ. बी.सी. सिन्हा, व्यावसायिक पर्यावरण, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स
4. प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकांक अर्थशास्त्र
5. रमेश सिंह, भारतीय अर्थव्यवस्था, मेक ग्रीव हील एजुकेशन

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

Edit with WPS Office

International Journal of
Advances in Social Sciences
(IJASS)

ISSN -2347-5153 (Print)
ISSN - 2454-2679 (Online)

Volume 04, Issue 02, April- June, 2016

ADMINISTRATIVE, EDITORIAL, ADVERTISING AND SUBSCRIPTION OFFIC

A and V Publications, RJPT House, Lokmanya Grih Nirman Society, Rohanipuram,
In-front of Sector- 1, Pt. Deendayal Upadhyay Nagar, Raipur 492 010. (CG) India.
Phone No. +919406051618. E. mail: editor.rjhss@gmail.com; Website: www.anvpublication.org

Edit with WPS Office

International Journal of
Advances in Social Sciences

ISSN 2347- 5153
Volume 04, Issue 02, April- June, 2016

CONTENT

- **A Study About Effect of Socio Economic Trends on Students**
  Dr. Paras Jain, Dr. Rajesh Shrivastav 55
- **An Analytical Study on Determining the Effect of Joining the Self Help Group in Improving the Economic Status of Women in Nagri Block of Dhamtari District, Chhattisgarh**
  Ku. Nisha Diwan, Dr. Mandeep Khalsa 58
- **BRICS Countries Farm Trade Performance**
  Kiran Bala Das, Dr. Ravindra Brahme 61
- स्वयं सहायता समूह, लघु ऋण एवं महिला सशक्तिकरण – एक अध्ययन
  शशि पाण्डेय 64
- रायपुर क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र में बाल–श्रमिक के मजदूरी का आर्थिक अध्ययन
  Dr. (Mrs.) Aradhana Shukla 69
- सर्वेक्षित ग्रामों में भूमि उपयोग एवं शस्य प्रतिरूप
  Dr. Pritibala Chandrakar 71
- जिला सहकारी कृषि बैंक के वित्तीय विवरण का विश्लेषण (दुर्ग जिले के संदर्भ में)
  डॉ. नरेन्द्र कुमार देवांगन 78
- **Training, Opportunities and Challenges of Accredited Social Health Activists for providing Maternal and Child Health care in Murshidabad district of West Bengal**
  Kunal Kanti De, Dan Amitabh, Roy Bibhash, Pasi A R, Jalaluddeen M 84
- रायपुर संभाग के औद्योगिक विकास में जिला उद्योग केन्द्रों का योगदान (दुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में)
  डॉ. हेमलता साहू 89
- **Changing Pattern of Population Density: A Case Study of Sample Village Ambedkarnagar District**
  Dr. Alok Pandey, Dr. Chandra Shekhar Dwivedi 96
- रायपुर जिले की कृषि वित्त व्यवस्था में राष्ट्रीयकृत बैंकों का योगदान - एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
  डॉ. किशोर कुमार साहू 101
- **Contribution of Socio-Religious Reform Movement to attain the Social Justice in Indian Society**
  Sanjeev Kumar 107
- **Saving and Investment pattern of Farm Households under Imperfect Rural Credit Markets**
  Dr. Poonam Singh 111
- न्यायिक सक्रियता बनाम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत
  अनेक कुमार साहू एवं खान 119
- **Education for Women Emancipation: Swami Vivekananda in Today's Relevance**
  Dr. Barnali Maity 122
- **Urbanisation in India: Trends and problem**
  Dr. (Mrs.) Archana Sethi 129
- **Instruction to Authors** 133

Edit with WPS Office

www.anypublication.org

ISSN 2347-5153 (Print)
2454-2679 (Online)

RESEARCH ARTICLE

रायपुर क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र में बाल–श्रमिक के मजदूरी का आर्थिक अध्ययन

Dr. (Mrs.) Aradhana Shukla
Assistant Professor, Commerce, Radhabai Navin Kanya Mahavidyalaya, Raipur CG
*Corresponding Author E-mail: **saiaradhna09@gmail.com**

ABSTRACT:
किसी देश के बच्चों की अच्छी या बुरी दशा की वहाँ की संस्कृति स्तर का सबसे विश्वसनीय मापदण्ड होता है। बालक, मानव–इतिहास का निर्माण एवं मानव जीवन का नींव है, उसका सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है।

KEYWORDS: बाल–श्रमिक, मजदूरी

प्रस्तावना –
बच्चे की जो आयु स्कुल की बेंच पर बैठकर अपना पाठ याद करने और समझने की होती है, खेल की बगिया में मुस्कहरटो के फूल बिखरने की होती है, उसी अल्प आयु में बहुत से देष के मासूम बच्चे होटल या रेस्टोरेंट में काम करते है।

हमारे देष में वर्तमान में बाल मजदूरों की संख्या लगभग 7 से 8 करोड़ है, जिनकी आयु 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक है। प्रतिवर्ष बाल दिवस अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर मनाते अथवा राष्ट्रीय स्तर पर किंतु बाल श्रमिक की संख्या पर कदाचित ही उसका कोई प्रभाव पड़ता है, इन कार्यकमों में केवल स्कूली बच्चे एवं संभ्रात परिवार के बच्चे ही हिस्से लेते है, किंतु बाल श्रमिक नहीं होते बच्चे अंधकारमय भविष्य के साथ जीवन निर्वाह करते हुए अपने माँ–बाप के बुढ़ापे की लाठी बने हुए ।

Received on 11.04.2016 Modified on 12.05.2016
Accepted on 04.06.2016 © A&V Publication all right reserved
Int. J. Ad. Social Sciences 4(2): April- June, 2016; Page 69-70

हमारे यहाँ गरीबी अभिशाप है, जिसका प्रमुख कारण निरंतर बढ़ती हुयी बच्चों की संख्या ही कहा जायेगा। अतः चिड़िया के चूजों की तरह गरीब तुनबे के बच्चों के पर असमय ही निकलने लगते हैं, और काम की तलाष में अपने घरों से फुर्र होकर खतरनाक उद्योगो में भी काम तलाषने लगते है।

अध्ययन का क्षेत्र –
यह शोध पत्र रायपुर नगर के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बाल श्रमिको का आर्थिक विष्लेषण किया गया है।

ऑकड़े का संग्रहण –
यह शोध पत्र मुख्य रूप से प्राथमिक संमको पर आधारित है। कार्यलय, श्रमायुकत रायपुर नगर द्वारा किये सर्वे के अनुसार असंगठित क्षेत्र में बाल – श्रमिको की कुल संख्या 657 ज्ञात की गयी जिसमें 302 लड़के तथा 355 लड़किया थी। कार्यरत बाल–श्रमिक जिन व्यावसायो में संलग्न है उन

Edit with WPS Office

Edit with WPS Office

October To December 2017
E-Journal, Volume IV, Issue XX
U.G.C. Journal no. 64728

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 4.710 (2016)

Naveen Shodh Sansar

(An International Multidisciplinary Refereed Journal)
(U.G.C. Approved Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

Edit with WPS Office

210. Production Problems of Horticulture Sector in Jammu and Kashmir: A Case Study of District Anantnag (Mushtaq Ahmad Khan, Dr. K.K.Vaidya) 615
211. Sports Competition Anxiety of University Level Badminton Players of Haryana and Rajasthan (Dr. Ravi Kumar, Jaswinder Singh) 619
212. हिन्दी कहानी के दलित साहित्य : स्वरूप तथा दशा व दिशा (दशरथ) 622
213. नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक में आधुनिक बैंकिंग सेवा (गोपाल कुरील, डॉ. सुनील मोरे) 625
214. An Overview On Cyber Space & Security (Dr. Neena Pyasi) 628
215. A Hybrid Inteligent System For Legal Reasoning (Dr. Pooran Singh, Prof. Neeraj Bhargava, Parul Baghla) 631
216. Image Compression Using Digital Wavelet Transform With Global Hard Thresholding (Brij Mohan Pareek, Dr. Amit Kumar Vyas) 634
217. पर्यावरण सचेतना और विद्यार्थियों का पर्यावरणीय संज्ञान (किरण पवार, डॉ. साधना देवेश वर्मा) 641
218. भारत की ग्रामीण शासन व्यवस्था तथा जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली एवं राजनीतिक जागरूकता की स्थिति (सर्वेक्षण पर आधारित अध्ययन) (डॉ. हितेन्द्र यादव) 644
219. Human Resource Development Policies in Public Sector and Private Sector Banks (Dr. Jaspreet Singh Mujral, Gurpreet Kaur) 647
220. Effect of Cyber Crime on Bank's Finances (Neeta, Pankaj Kumar) 650
221. GST and its Impact (Yogesh Kumar Swami) 653
222. E-Marketing- its Impact on Indian Society(Dr. Vijay Prakash Mishra) 655
223. महिला बेरोजगारी उन्मूलन में स्वसहायता समूह की भूमिका का अध्ययन (बिलासपुर जिले के कोटा ब्लाक के ग्राम पंचायतों के विशेष संदर्भ में)(नेहा सिंह, डॉ. ऋचा यादव) 661
224. Chakravyuh Challenges of the Indian Economy (Dr. P.K. Sirothia) 664
225. Glitches in the Way of Good Governance of India (Mukhtar Ahmad Lone, Dr. Niraj Kumar Jha) 667
226. Engagement of United Nations on the Kashmir Conflict (Mudasir Ahmad Bhat, Dr. Ravi Ranjan) 670
227. A Study on Women Entrepreneureship in Ujjain District (Asmita Jain, Dr. Rakesh Dhand) 673
228. Decomposition Analysis of Horticulture Sector in the State of Jammu and Kashmir (Rather Tajamul Islam, Mudasir Amin) 677
229. Variability in Horticulture Sector of Jammu and Kashmir – India : A Study of Two Decades (Rather Tajamul Islam) 680
230. मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फर का साहित्यक योगदान (डॉ. नीलम सोनी) 684
231. Role of Regional Rural Banks in the Development of India (Vijay Kumar Gupta) 687
232. Effect of Food Habits, Gender and their interaction on Academic Performance of College going students of Indore division of Madhya Pradesh (Dr. Sushama Sharma, Priyanka Gehlot) 690
233. समसामयिक भारत में दलित उत्पीड़न एवं सामाजिक न्याय प्रस्थिति (महेश कुमार रचियता, डॉ. सुनील महावर) 694
234. सरकारी एवं निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत युवाओं का शैक्षणिक प्रदर्शन (डॉ. बी.के. गुप्ता) 697
235. सरदार पटेल की बारदोली सत्याग्रह आन्दोलन में भूमिका (डॉ. मनोज दाधीच, जयश्रीबेन डी. मेंवाड़ा) 700
236. योग – समुत्कर्ष एवं नि:श्रेयस का अद्भुत रहस्य (डॉ. दिनेश कुमार कौशल) 704
237. वाल्मीकि रामायण में पत्नी का स्वरूप (डॉ. पंकज कुमार सिंह) 706
238. आदिकवि वाल्मीकि द्वारा नारी वर्णन (डॉ. पंकज कुमार सिंह) 708
239. Effects Of Various Teaching Methodology On Schools Students (Lokesh Jain) 712
240. Preferred Payment Options after Demonetization in India (Dr.Yadu Rao) 714
241. पर्यावरण संरक्षण एवं हमारा दायित्व (डॉ. शुभा तिवारी) 719
242. भवन निर्माण में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों के लिए संचालित की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मूल्यांकन (उषा राजे, डॉ. महेश गुप्ता) 721

243. भारत की गरीबी निवारण योजनाओं का मूल्यांकन (डॉ आराधना शुक्ला, निधी श्री) 725
244. रामायण और आधुनिक काल में दाम्पत्य की अवधारणा व स्वरूप (डॉ. अभयवीर) 727

Edit with WPS Office

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) Jan. To March 2018 E-Journal, VOl. IV, Issue XXI

भारत की गरीबी निवारण योजनाओं का मूल्यांकन

डॉ. आराधना शुक्ला* निधी श्री **

शोध सारांश – भारत देश में गरीबी आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा बनती जा रही है अतः विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन के पूर्व सरकार के द्वारा गरीबी निवारण अनेक योजनायें संचालित की जा रही है। ताकि जनता के पास क्रय शक्ति सृजित हो और उनके द्वारा देश के आर्थिक विकास के आवश्यक पहलू बचत व निवेश पर योगदान दिया जा सके।

शब्द कुंजी – गरीबी, आर्थिक विकास एवं गरीबी निवारण योजनायें।

प्रस्तावना – कोई भी देश आर्थिक गति तभी पाप कर सकता है जब उस देश की जनता के पास पर्याप्त आय प्राप्ति के साधन हो कि वह अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। किन्तु भारत जैसे विकासशील देश के आर्थिक विकास में प्रमुख बाधक तत्व गरीबी अथवा निर्धनता है अतः देश की सरकार का सर्व प्रथम दायित्व जनता की गरीबी हटाना होता है। गरीबी निवारण हेतु सरकार अनेक योजनायें संचालित कर रही है जो मुख्य रूप से जनता को न केवल आय का साधन प्रदान कर रही है बल्कि उन्हें स्वरोजगार के अवसर भी दे रही है। जैसे :– मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना, जनश्री बीमा योजना, अंत्योदय अन्य योजना आदि।

गरीबी निवारण संचालित योजनाओं से गरीब जनता को आय एवं रोजगार प्राप्ति के अनेक स्रोत प्राप्त होते हैं तथा तथा कौशल विकास योजनाओं से जनता को आय व रोजगार की प्राप्ति होगी परिणाम स्वरूप बचत व निवेश भी प्रोत्साहित होगी और देश का आर्थिक विकास संभव हो जायेगा।

अध्ययन का उद्देश्य – शोध पत्र अध्ययन के उद्देश्य अग्रांकित है–

1. देश में गरीबी का अध्ययन करना।
2. संचालित विभिन्न गरीबी निवारण कार्यक्रमों की उपलब्धि का अध्ययन करना।
3. विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के गरीबी पर प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना :

1. विभिन्न गरीबी निवारण योजनाओं से गरीबी का स्तर कम हो रहा है।
2. गरीबी निवारण योजनायें देश की गरीबी हटाने में प्रभावकारी है।

शोध प्रविधि – भारत देश की सरकार के द्वारा संचालित गरीबी निवारण योजनायें वास्तव में गरीबी निवारण में प्रभावकारी है अध्ययन नहीं इस तथ्य के विश्लेषण हेतु भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के द्वारा संचालित द्वितीयक आंकड़ों का अध्ययन किया गया है।

शोध साहित्य का पुनरावलोकन :

1. बालकृष्ण बी. 1943 इन्होंने अनेक क्षमाकीय योजनायें विशेषकर विपणन संबंधी योजनाओं पर अध्ययन कर यह निष्कर्ष प्रकट किया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की संस्थाना के आधार पर विपणन संबंधी योजनायें संचालित करती है।
2. ग्रामीण विकास मंत्रालय पोर्टल से प्रकाशन कॉलम के वार्षिक रिपोर्ट एवं पहल व उपलब्धियों के द्वारा हमें वर्तमान में चल रही सरकार की ग्रामीण विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई एवं इन गतिविधियों के ग्रामीण निर्धनों के उपर प्रभाव तथा उनके फायदे के बारे में जाना। यह जानकारी हमें हमारे रिसर्च पेपर हेतु बहुत ही सहयोगी रही है।

शोध अध्ययन – भारत में देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय कम होना ही यहां कि निर्धनता का प्रमुख कारण है। साथ साथ ही यह कहा जा सकता है कि देश में गरीबी के प्रमुख कारण मुख्यतः रोजगार अवसरों में धीमी वृद्धि, निम्न आय अर्जन, जनसंख्या में भारी वृद्धि, दोषपूर्ण आर्थिक नीति आदि रहा है।

तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं से ही देश में गरीबी निवारण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है उनका प्रभाव गरीबी निवारण पर प्रभाव दिखाई देने लगा है तथा गरीबी के आंकड़ों में दिन प्रतिदिन आंशिक सुधार हो रहा है जो अग्रांकित आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा है:–

भारत में निर्धनता अनुपात एवं निर्धनों की संख्या

वर्ष	निर्धनता अनुपात (प्रतिशत में)	निर्धनों की संख्या (करोड़ में)
2004–05	37.2	40.71
2009–10	29.8	35.47
2011–12	21.9	26.93
2014–15	24.5	36.93

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत देश में निर्धनता की अनुपात 2004–05 में 37.2 प्रतिशत तथा वह घटकर 2011–12 में 26.93 करोड़ रह गया किंतु 2014–15 में निर्धन अनुपात एवं निर्धनों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण दोषपूर्ण आर्थिक नीती, मुद्रा प्रसार एवं मुख्य वृद्धि रही है।

सुझाव एवं निष्कर्ष – शोधकर्ता ने गरीबी निवारण संबंधी योजनाओं के सफल संचालन एवं परिणाम प्राप्त करने के लिए निम्न सुझाव दिया है :–

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) आर. आई. टी. महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) प्रगति महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) Jan. To March 2018 E-Journal, VOl. IV, Issue XXI

1. भारत जैसे कृषि प्रधान देश हेतु बहुउत्पादी कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण से संबंधित योजनाओं जैसे सड़क निर्माण, कुआं, नहर, आवास, विद्युत संबंधित संचालित किया जाना चाहिए।
3. कौशल विकास योजनाओं का उचित तरीके से संचालन किया जाना चाहिए।
4. योजनाओं से संबंधित जानकारी जन समान्य तक सुलभ तरीके से पहुंचाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ जे.पी. मिश्रा, 'व्यावसायिक पर्यावरण', साहित्य पब्लिकेशन, पेज क्रमांक 88–89
2. डॉ बी.सी. सिन्हा, 'व्यावसायिक पर्यावरण', संजय साहित्य पब्लिकेशन, पेज क्रमांक 208
3. 'भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट'
4. सिन्हा बी.सी., 'राजस्व एवं रोजगार के सिद्धांत', पेज क्रमांक 108–110
5. पुरी एवं मिश्रा, 'भारतीय अर्थशास्त्र', पेज क्रमांक 69
6. WWW.FING.GOV.IN, INDIA

Edit with WPS Office

Volume 6 | Issue 2 | April- June | 2018 ISSN-2347-5153

IJASS

International Journal of Advances in Social Sciences

An International Peer- reviewed Journal of Social Sciences

Edit with WPS Office

International Journal of
Advances in Social Sciences

ISSN 2347- 5153
Volume 06, Issue 02, April- June, 2018

CONTENT

- डॉ. कुन्तल गोयल – सेवा से सृजन तक
  डॉ. बृजेन्द्र पाण्डेय, शैली ओझा 91
- **Social Audits in India: A Long Way to Go**
  Dr. Suchitra Rathi 96
- छ.ग. नगर पालिक निगमों के द्वारा प्रदान किये गये सुविधाओं का विश्लेषण(रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग नगर पालिक निगम के विषेष संदर्भ में)
  डॉ. आराधना शुक्ला, डॉ. अशोक शर्मा 100
- **Reflection of Aśoka: His Idea of Dhamma in Pillar Edict Seven**
  Ashu J 104
- **MGNREGS: Socio-Economic Impact on The Rural E**
  Ram Prasad Chandra, Dr. Ravindra Brahme 109
- **Eculiteracy: Educating for tomorrow**
  Dr. Saumnya Tiwari 113
- **Role of Television in Development-A Study on Kadapa District**
  G. Rama Sudha 115
- आय एवं रोजगार के सृजन में खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं का मूल्यांकन(एक अध्ययन राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में)
  श्रीमती दीपा देवांगन, डॉ. के. एल. टांडेकर 121
- भारत में गरीबी उन्मूलन एवं खाद्य सुरक्षा
  डॉ.वीरेन्द्र सिंह सट्टसेनिया, डॉ. बी. एल. सोनेकर 125
- मुरिया जनजाति में तत्वदृष्टि एवं जीवनदृष्टि : दार्शनिक आयाम
  Dr. Nister Kujur 131
- **Role of Innovation Strategy in Organizational Success-The case of Micromax Informatics Ltd.**
  Dr. Anagha K 139
- **Instruction to Authors** 143

Edit with WPS Office

ISSN 2347-5153 (Print)
2454-2679 (Online)

Vol. 06| Issue-02|
April- June 2018

Available online at
www.anvpublication.org

International Journal of Advances in Social Sciences

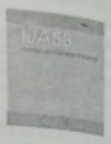

RESEARCH ARTICLE

[1]सहाप्राध्यापक वाणिज्य, आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज, रायपुर (छ.ग.)
[2]सहाप्राध्यापक वाणिज्य, जे.योगानंदम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
*Corresponding Author E-mail: **saiaradhna09@gmail.com**

ABSTRACT:
भारत में संघीय शासन प्रणाली प्रचलित है. तथा संघीय शासन व्यवस्था की सबसे सुक्ष्म शासन व्यवस्था जो जनता से प्रत्यक्ष जुड़ी रहती है उसे स्थानीय सत्ता कहते है। स्थानीय स्वषासन मुख्यतः नगरों की देखभाल करने वाली संस्थाऐ होती है जिन्हे वर्तमान में नगर पालिक निगम कहते हैं , जिनका प्रमुख कार्य स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर एवं रहन सहन मे सुधार लाने हेतु मूलभुत सुविधाओं की स्थानीय शासन व्यवस्था के द्वारा उपलब्ध करायी जाती है तो निष्चित तौर पर आम जनता को शनैः शनैः उच्च जीवन स्तर प्राप्त होता जायेगा ।

KEY WORDS: नगर पालिक निगम के द्वारा प्रदत्त सुविधायें ।

INTRODUCTION:
प्रजातंत्र की केन्द्र बिंदु ''स्थानीय सत्ता'' होती है यदि इसे लोकतंत्र की ''आत्मा '' कहा जाये तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी । यदि जनहित का संपूर्ण कार्यभार यदि राज्य पर सौंपा जाये तो कार्यों की अधिकता एवं कार्यभारार्पण के बोझ तले राज्य दब कर रह जाता है , अतः राज्य के जनहित के कार्यो का सुनियोजित निर्वहन हेतु राज्यीय कार्यभार का विकेन्द्रीयकरण करते हुए स्थानीय सत्ता या ''नगर पालिक निगम'' की स्थापना अनिवार्य हो जाती है। योजना आयोग में कहा गया है कि विकास के क्षेत्र में स्थानीय संस्थायें प्रगति के सेतु जैसे ही है।

Received on 12.03.2018 Modified on 25.04.2018
Accepted on 29.04.2018 © A&V Publication all right reserved
Int. J. Ad. Social Sciences. 2018; 6(2):100-103.

''स्थानीय स्वशासन के स्थापना के उद्देश्य को निम्न बिंदुओं में व्यक्त किया गया हैं:—स्थानीय नागरिकों की समस्याएँ यथा पेयजल, विद्युत, सड़क, नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का निवारण स्थानीय प्रशासन कुशलता से कर सकता है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगमों के द्वारा (रायपुर बिलासपुर एवं दुर्ग नगर पालिक निगम के विशेष संदर्भ) जनता को प्रदान की गई प्रमुख सुविधाओं के संतुष्टि का विश्लेषण अग्र तालिका में दी गई है —:

तलिका क्रं. 1
शिक्षा सुविधाएँ

क्र.	नगर पालिक निगम	संतुष्ट	असंतुष्ट	औसत	कुल
1	रायपुर	47.18%	20.4%	32.4%	100
2	बिलासपुर	23.1%	63.87%	13.03%	50
3	दुर्ग	37.25%	43.12%	19.63%	50

Edit with WPS Office

उक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि नगर से लाभान्वित जनता तुलनात्मक रूप में रायपुर पालिक निगमों के द्वारा प्रदत्त शिक्षा सुविधा नगर पालिक निगम सर्वाधिक संतुष्ट है ।

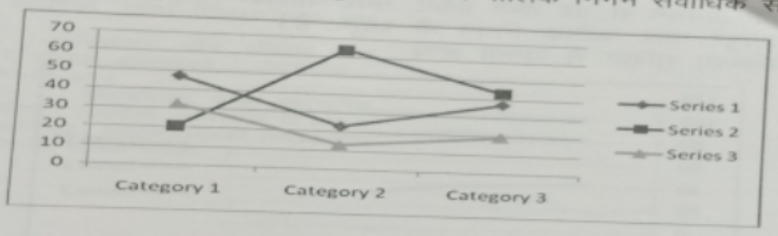

तलिका क्रं. 2

2.स्वच्छता सुविधाएँ

क्र.	नगर पालिक निगम	संतुष्ट	असंतुष्ट	औसत	कुल
1	रायपुर	32.11%	58.47%	9.42%	100
2	बिलासपुर	43.25%	38.15%	18.6%	50
3	दुर्ग	63.22%	28.25%	8.53%	50

उक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि नगर नगर पालिक निगमों की तुलना में दुर्ग नगर पालिक निगमों के द्वारा प्रदत्त .स्वच्छता पालिक निगम में संतुष्ट है । सुविधा से लाभान्वित जनता अपेक्षाकृत अन्य

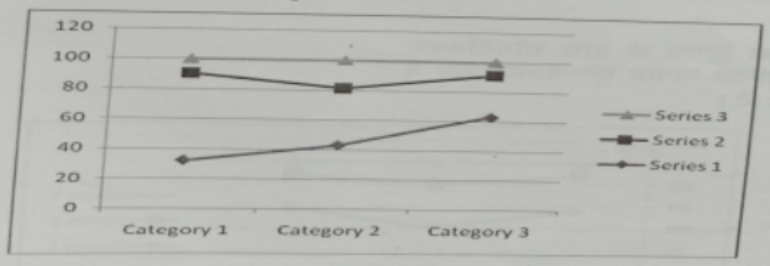

तलिका क्रं. 3

3.चिकित्सा सुविधाएँ

क्र.	नगर पालिक निगम	संतुष्ट	असंतुष्ट	औसत	कुल
1	रायपुर	42.37%	38.25%	19.38%	100
2	बिलासपुर	37.25%	48.23%	14.52%	50
3	दुर्ग	25.12%	48.26%	26.62%	50

Edit with WPS Office

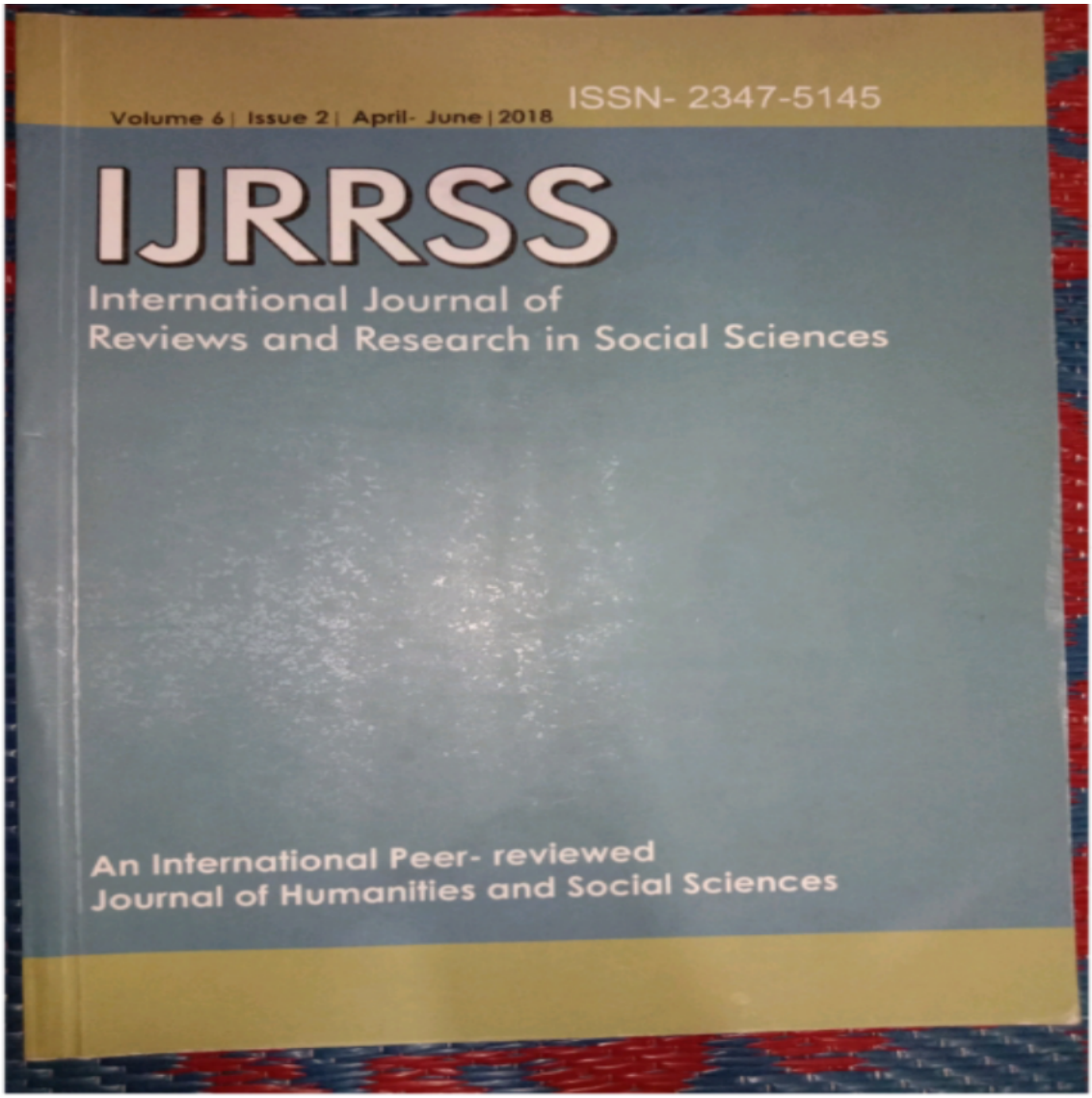

Edit with WPS Office

International Journal of
Reviews and Research in Social Sciences (IJRRSS)
ISSN 2347-5145 (Print)
ISSN 2454-2687 (Online)
Volume 06, Issue 02, April- June, 2018

CONTENT

- पंडित स्वराज्य प्रसाद त्रिवेदी के नाटकों का विश्लेषण
  डॉ. बृजेन्द्र पांडेय, श्रीमती सीमा बंद्राकर 103
- छ.ग. के नगर–पालिक निगमों के बजटीय स्थिति का विश्लेषण (रायपुर बिलासपुर दुर्ग के विशेष संदर्भ)
  डॉ. आराधना शुक्ला 108
- A study of Chhattisgarh's export performance during 2004-05to 2011-12
  Dr. Nilesh Kumar Tiwari 112
- भारतीय स्कूलों की वर्तमान परिदृश्य
  खोमन लाल साहू 115
- मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास 'इदन्नमम' में नारी–[illegible]
  डॉ. बृजेन्द्र पांडेय, शिवेश्वर प्रसाद टण्डन 118
- कार्यशील पूँजी दिवस की अवधारणा
  डॉ. आराधना शुक्ला, डॉ. अशोक शर्मा 123
- Railway Disasters in India: Causes, Effects and Management
  Satish Bhagwatrao Aher, Deepak Raj Tiwari 125
- सीमान्त वर्ग में शिक्षा के स्वरूप का अध्ययन
  श्रीमती रजनी 133
- Compliance of Competition Law: A Corporate Perspective
  Biranchi Narayan P. Panda 141
- भारत में टमाटर उत्पादन के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता की प्रवृत्ति(2004–05 से 2013–14)
  कु. तीपा तिवारी 148

Edit with WPS Office

ISSN 2347-5145 (Print)
2454-2687 (Online)

Available online at
www.anvpublication.org
International Journal of
Reviews and Research in Social Sciences

Vol. 06| Issue-02|
April- June 2018

RESEARCH ARTICLE

सहाप्राध्यापक वाणिज्य, आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज, रायपुर (छ.ग.)
*Corresponding Author E-mail: saiaradhna09@gmail.com

ABSTRACT:
बजट किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, सारांष पत्रक होता है। स्थानीय सत्ता को प्रमुख कार्य स्थानीय विशेष के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय करती है, इस हेतु अनेक स्त्रोतों से आय प्राप्त विश्लेषणात्मक अध्ययन हेतु बजटीय स्थिति का विश्लेषणात्मक होता है।

KEYWORDS: बजटीय स्थिति, विश्लेषण

नगर पालिक निगम एक स्थानीय प्रशासन होता है। भारत के संविधानिक नियमानुसार जब किसी स्थान (शहर की) जनसंख्या 2 लाख या इससे अधिक होती है तो स्थानीय सत्ता की शासन की बागडोर नगर पालिक निगम के हाथों में होती है। भारत में त्रीस्तरीय पंचायती शासन प्रणाली है, इसके तहत नगर प्रशासन वर्ष 1966 से ही अस्तित्व में आया है। भारत का प्रथम नगर – निगम मद्रास नगर निगम 1687 है। नगर निगम के कार्यो को प्रमुख 4 भागों में विभाजित किया जाता है (अ) सार्वजनिक रक्षा (ब) सार्वजनिक स्वास्थ्य (स) सार्वजनिक शिक्षा (द) सार्वजनिक सुविधाए

उक्त व्ययों की दायित्व निगम के द्वारा विभिन्न शीर्षकों से आय प्राप्त करती है, यथा– संपत्ति कर, सवारी गाडि.यों पर कर, चुंगी कर, मकान कर, पानी व बिजली कर राज्य के सहायता, ऋण व्यापार आदि। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत नगर पालिक निगमों के द्वारा बजट के प्रमुख पत्र बनाया जाता है। विगत 10 वर्षो के द्वारा बनाये गये बजट का विश्लेषणात्मक अध्ययन अग्राकिंत किया गया है।

Received on 29.04.2018 Modified on 18.05.2018
Accepted on 02.06.2018 © A&V Publications All right reserved
Int. J. Rev. and Res. Social Sci. 2018; 6(2):108-111.

Edit with WPS Office

तलिका क्रमांक — 1.1
रायपुर नगर निगम की बजटीय स्थिति का अध्ययन

1 वर्ष	2 कुल आय (रू.में)	3 कुल व्यय (रू.में)	4 अतिरेक (रू.में)	5 घाटा (रू.में)
2005—06	25468.65	27874.57	-	2405.92
2006—07	28267.7	31091.2	-	2823.5
2007—08	48930.05	53216.58	-	4286.53
2008—09	25497.27	30600.79	-	5103.52
2009—10	62649.84	80213.31	-	17563.5
2010—11	81015.6	88032.34	-	7016.74
2011—12	44441.2	33340.49	11100.71	-
2012—13	30572.05	33898.37	-	3326.17
2013—14	59838.46	52631.54	7206.92	-
2014—15	183236.29	209709.7	-	26473.4
2015—16	194611.99	222230.74	-	27618.8
$\bar{x}$	71320.82727	78439.96636	-	-
σ	60800.42553	71000.17632	-	-
C.V.%	85.24918717	90.51530695	-	-

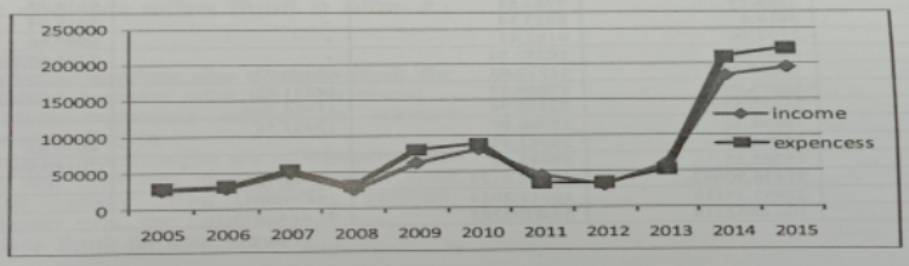

तलिका क्रमांक — 1.2
दुर्ग नगर निगम की बजटीय स्थिति का अध्ययन

1 वर्ष	2 कुल आय (रू.में)	3 कुल व्यय (रू.में)	4 अतिरेक (रू.में)	5 घाटा (रू.में)
2005—06	2419.1051	2825.54326	-	406.43816
2006—07	3335.50102	3531.30652	-	195.8055
2007—08	5068.039	4294.57697	773.46203	-
2008—09	5341.97	5541.44904	-	199.47904
2009—10	4200.247	6772.27	-	2572.023
2010—11	6404.326	4332.9305	2071.3955	-
2011—12	7389.611	4911.27189	2478.33911	-
2012—13	9928.983	8354.33524	1574.64776	-
2013—14	7225.923	7630.1404	-	404.2174
2014—15	7514.252	8313.221	-	798.969
2015—16	13264.572	9955.153	3309.419	-
$\bar{x}$	6553.866284	6042.01798	2041.45268	
σ	3085.285086	2302.74333	951.999479	
C.V.%	47.07580155	38.1121562	46.6334336	

Edit with WPS Office

ISSN 2347-5145 (Print)
2454-2687 (Online)

Vol. 06| Issue-02|
April- June 2018

Available online at
www.anvpublication.org
International Journal of
Reviews and Research in Social Sciences

RESEARCH ARTICLE

कार्यशील पूँजी दिवस की अवधारणा

डॉ. आराधना शुक्ला[1], डॉ. अशोक शर्मा[2]
[1]सहाप्राध्यापक वाणिज्य, आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज, रायपुर (छ.ग.)
[2]सहाप्राध्यापक वाणिज्य, जे.योगानंदम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
*Corresponding Author E-mail: saiaradhna09@gmail.com

ABSTRACT:
एक कंपनी अपने व्यापार के संचालन हेतु आवश्यक पूंजी लगाती है जैसे की कच्चे मॉल क्रय , निर्मित मॉल को उधार पर देना जिसके कारण उसकी देनदारी में पूंजी कुछ समय के लिए फंस जाती है, कार्यशील पूँजी दिवस की गणना से हमे ज्ञात होता है कि कितने दिनों में ये पूंजी कंपनी को वापस मिल सकती है। यदि कार्यशील पूंजी कंपनी को शीघ्र वापस मिल जाती है तो इसका अर्थ है कि कंपनी के वित्तीय हालत बेहतर है । और उसे रोजमर्रा के काम काज चलाने मे कोई दिक्कत नहीं आएगी ।

KEYWORDS: कार्यशील पूँजी दिवस

प्रस्तावना —

व्यवसाय के संचालन से सम्बन्धित दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ सम्पत्तियों की आवश्यकता होती हैं। इन सम्पत्तियों में रोकड़ , प्राप्त विपत्र , विनियोग , कच्चा माल एवं अल्पकालीन ऋण आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन सम्पत्तियों में विनियोजित पूंजी को कार्यशील पूंजी को कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के आवश्यकताओं की पूर्ति एवं प्रगति हेतु स्थिर सम्पत्तियों के लिए भी पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करती है। किसी भी कोष की प्राप्ति जो चालू सम्पत्तियों को बढ़ाता है। उस कोष को कार्यशील पूँजी की संज्ञस दी जाती है।

Received on 28.04.2018 Modified on 12.05.2018
Accepted on 20.05.2018 © A&V Publications All right reserved
Int. J. Rev. and Res. Social Sci. 2018(2):123-124.

कार्यशील पूंजी प्रबन्ध — व्यवसाय में पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजर का होना आवश्यक है। इस दृष्टि से व्यवसाय की परिस्थितयों को ध्यान में रखतें हुए कार्यशील पूंजी के प्रबन्ध का उद्देश्य संस्था की चालू सम्पत्तियों एवं चालू दायित्वों के मध्य इस प्रकार सामंजस्य स्थापित करना होता है कि, कार्यशील पूंजी की मात्रा का निर्धारण अनुकूलतम हो सके । अतः कार्यशील पूंजी की मात्रा का निर्धारण अनुकूलम हो सके । अतः कार्यशील पूंजी का प्रबन्ध वित्तीय प्रबन्ध का आंतरिक भाग है। इसलिए कार्यशील पूंजी का प्रबन्ध एक संस्था के आर्थिक स्त्रोतों पर नियंत्रण करने एवं उसकी लाभदायिकता को बनाये रखने में सहायक सिद्ध होता हैं कार्यशील पूंजी का प्रबन्ध उस संस्था की जोखिम, तरलतर एवं लाभदायिकता के बीच सही सामंजस्य बनाए रखने में सहायता करता है।

Edit with WPS Office

कार्यशील पूंजी दिवस के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि देनदारी की वापसी कितने दिन मे होता है । जिसकी गणना निम्न सूत्र कि जाती है –

कार्यशील पूंजी दिवस= कार्यशील पूंजी / 365 / विक्रय

निम्न तालिका में चार चुने हुए कंपनी के कार्यशील दिवस का विश्लेषण किया जा रहा है।

Company	Mar-07	Mar-08	Mar-09	Mar-10	Mar-11	Mar-12	Mar-13	Mar-14	Mar-15	Mar-16
Vardhman Textiles	179	180	177	209	203	162	192	177	149	169
Trident	121	72	53	93	108	96	97	75	89	109
KPR Mills	179	180	177	89	122	71	64	67	69	111
Indo Count	138	129	-60	-37	11	13	38	60	56	64

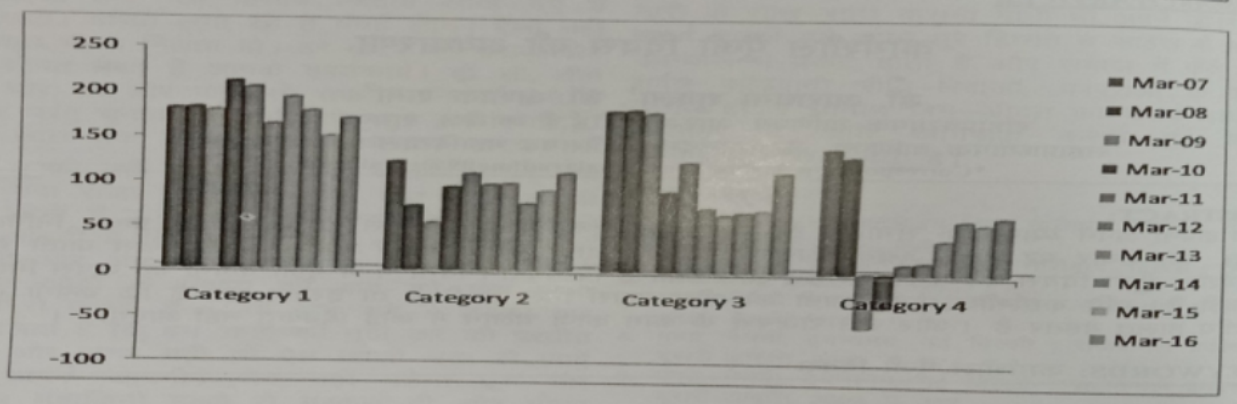

ऊपर दी हुई चारो कंपनियों की कार्यशील पूंजी की अवधारणा देख कर ये पता लगता है की वर्धमान टेक्सटाइल्स अपनी पूंजी औरो के मुकाबले ज्यादा दिनों के लिए बिज़नेस मे फंसा के रखती है। इसका अर्थ यह है की जिन ग्राहकों को कंपनी अपना माल बेचती है को काफी दिनों के बाद उधार चुकता करते है अर्थात कंपनी के ग्राहक वृहद मात्रा मे कंपनी के उत्पाद का क्रय करते है अतः भुगतान मे समय लगता है। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि कार्यशील पूंजी दिवस ना केवल देदारी वापसी की अवधि अपितु उपभोताओं की स्थिति का अध्ययन किया जा सकता है।

REFERENCES:

1. वशिष्ठ, जे. कल्याणी पब्लिकेशन,''वित्तीय प्रबन्ध''
2. प्रतियोगिता दर्पण
3. गुप्ता के.एल. सहित्य भवन प्रकाशन

Edit with WPS Office

Volume III, Issue XXII
April 2018 E-Journal
U.G.C. Journal No. 64728

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 5.110 (2017)

Naveen Shodh Sansar

(An International Multidisciplinary Refereed Journal)
(U.G.C. Approved Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

Edit with WPS Office

36. विशिष्टाद्वैत वेदान्त में आत्म तत्व निरूपण (डॉ. दिनेश कुमार काशल) 100
37. बी.पी.एल. परिवार के विकास पर मनरेगा योजना के प्रभावों का मूल्यांकन (कविता यादव) 104
38. देवास जिले में ग्रामीण बाजार का बदलता स्वरूप (डॉ. सुनील मोरे, जाहिद खान) 108
39. भक्त कबीर विचारधारा (मनजीत कौर) 111
40. शिवप्रसाद सिंह की कहानियों में ग्रामीण समाज (कमलेश चौधरी) 114
41. A Study of Essential Skills by Experts and Students of Teacher Education : Suggested Strategies (Dr. Nirupama Sharma, Pratima Samar) 117
42. ग्रामीण बाजार के उपभोक्ताओं की समस्या (देवास जिले के विशेष सन्दर्भ में) (डॉ. सुनील मोरे, जाहिद खान) 120
43. खरगोन जिले में नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना एवं विकास – एक मूल्यांकनात्मक अध्ययन (डॉ. सुनील कुमार शर्मा, प्रतिभा शर्मा) 122
44. नगरीय भूमि उपयोग का बदलता प्रतिरूप : इन्दौर महानगर के संदर्भ में (स्थानिक–कालिक विश्लेषण 1981–2011) (हेमंत मण्डलोई) 124
45. रामायण काल में नारी का सौन्दर्य (डॉ. पंकज कुमार सिंह) 126
46. आदिवासी एवं गैर आदिवासी जिले के शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षकों की सांवेगिक बुद्धि का तुलनात्मक अध्ययन (मीना भुटेजा (कालरा)) 128
47. सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के छात्र एवं छात्रा शिक्षकों में तनाव के स्तर का तुलनात्मक अध्ययन (हेमन्त त्रिवेदी) 132
48. वाल्मिकि रामायण में कन्या का स्वरूप (डॉ पंकज कुमार सिंह) 134
49. कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का विकास (प्रीती रवि, डॉ. ए. के. पाण्डे) 136
50. Yoga as an Effective Alternative Management Intervention for Perceived Occupational Stress: An Overview (Altaf Hussain) 137
51. हिन्दी भाषा और भूमण्डलीकरण के दौर में हिन्दी का बाजार (डॉ. अभयवीर) 141
52. महिलाओं के विरूद्ध अपराध एवं कानून (मेहर डोडवे) 144
53. बिलासपुर संभाग में परिवहन तंत्र का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव (डॉ. काजल मोड़वा, सुष्टि शर्मा) 147
54. English For Specific Purposes : Paragraph Writing For Engineering Students in National Capital Region (Dr. Omprakash Upadhyay) 149

55. Concept And Application Of Promissiory Estoppel : A Critical Study With Indian Evidence Act And Legislation (Narender Dhaka) 152
56. Relevance of Cashless Economy in India (Dr.Yadu Rao) 155
57. लघु उद्योगों के विकास में जिला उद्योग केन्द्र का योगदान (नन्दना शिल्पकार, डॉ. ए.के. पाण्डेय) 159
58. भारत में ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत (डॉ. शुभा तिवारी) 161
59. पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच की भूमिका (धनेन्द्र कुमार, डॉ. वाय.बी. कसवे) 163
60. अलका सरावगी के कथा साहित्य में चेतना के विविध आयाम (सुनिता चौहान, डॉ. मंजुला जोशी) 165
61. Historical Analysis of Spread of Buddhism from India To Tibet (Dr. Shilpa Mehta) 167
62. भवन निर्माण में कार्यरत महिला श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मूल्यांकन (उषा राजे, डॉ. महेश गुप्ता) 170
63. कृषक की आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा की कृषक अभीष्ट (डॉ. प्रीति मुरड़िया) 172
64. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं भारत (डॉ. आराधना शुक्ला, निधी श्री) 174
65. Role of Management in Faculty Development (Dr. Prabhat Chopra) 175
66. असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों के मानवाधिकार (रवि प्रकाश चौधरी, डॉ. ए.बी. सोनी) 181
67. हिन्दी साहित्य में किन्नरों का यथार्थवादी चरित्र–चित्रण (डॉ. पिंकी मिश्रा) 183
68. Analytical Study Of Women Oriented Life Insurance Plans (Dr. Savita Agrawal, Dr. Monika Bapat, Dr. Venus Shah) 185

Edit with WPS Office

JASRAE_ISSUE_1_VOL_1...

Ignited Minds Journals

Internationally Indexed, Peer Reviewed & Refereed Journals, Approved and Indexed by UGC

Edit with WPS Office

7:25 12

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XV, Issue No. 1, April-2018, ISSN 2230-7540

Contribution of Industrial Sector's In Corporate Social Responsibility (CSR) In India

Dr. Aradhana Shukla[1]* Mrs. Nidhi Shri Shukla[2]

[1,2] Assistant Professor, Vipra Mahavidyalaya, Raipur (CG)

Abstract – As a developing country, India is at growing stage of its industries, agriculture, telecommunication and infrastructure. After adoption of LPG (Liberalization, privatization, globalization) during 1991, Indian economy opened to worldwide enterprises which to have pro's and con's as a threat to domestic industries but also brought immense of opportunity for growth of industries and other sector's. This lead the Indian economy to bring up new idea of corporate social responsibility so as to p0revent concentration of economy as well as to balanced development of overall nation. By this research paper we are going to analyze the contribution pattern of industry and application section of CSR in India

Keywords- Corporate Social Responsibility, Industrial Contribution.

----------x----------

INTRODUCTION

Corporate social responsibility is also stands for corporate sustainability, sustainable business, corporate conscience, corporate citizenship or responsible business.

But actually referred as type of international private business self-regulation whose main object is to contribute to societal goals of philanthropic (Dispensing or receiving aid from fund set aside for humanitarian purpose), Activist or charitable nature by engaging in or supporting volunteering or ethically oriented practices.

India is the first country across the world which made CSR as mandatory thereby amending the companies Act 2013, in April 2014.

According to the Companies (corporate social responsibility policy) Rule ,2014 under section 135, section 469(1) ,section 469(2) and other related section of rule:-

a) Companies having Net worth of Rs. 500 cr. or more.

b) Companies having turnover of Rs. 1000 cr or more.

c) Companies having net profit of Rs. 5 cr. or more.

Than companies crossing prescribed threshold are required to spend at least 2% of their average net profit for immediately preceding 3 financial year on CSR activities.

As per above rule all sectors of industries are contributing towards CSR for different Aid / Facilities/ section of societal economy which are dealt further.

OBJECTIVES

- To analyze expressly meaning and actualization of rule in india.
- To analyze CSR spending pattern of different corporate sectors.
- To find out maximum spending and least spending sector of indian industry.
- To analyze CSR application section of societal requirement.
- To find out most and least application area of CSR funds.

REVIEW OF LITERATURE

P. Harshavadhini and M. Kannappan (2017-18)- "Introspection of CSR in India".

In this they explained in endoscopic evaluation of CSR evolution at stage wise and its applicability as well.

Charted- Suneera tondon- "Indian Industries Spend Most And Least On Social Welfare".

www.ignited.in

This article and paper examined the parameters of most and least spending of different sectors for CSR in summarized manner.

RESEARCH METHODOLOGY

This research paper is an explanatory in pattern which is primary based on secondary sources such as article, books and websites for its data consideration.

STUDY OF CSR AND INDUSTRIES IN INDIA

CSR is an ethical term of business or industries which is used to represent the upliftment or development of deprived section of society by sharing one's earning who is well capable of evolution of CSR are as old as business or trade system in India:-

- Philosopher era- some of philosopher like koutilya promoted ethics and principles involvement in business activity and at that period of industrial system were pushed towards religious, charity as key moving factor

3. Outlook of investors for the perceptional decision making.

4. Labor turnover as well labor competitive market edge urge.

ANALYSIS

India is being more emphasized and focused as well with its CSR spending. As per the survey by KPMG India at year ended march 2018 CSR stood up Rs. 7536.30 cr. and also analyzation of top listed company of different sectors of India.

In 2018 CSR spending industries were 47% higher than spended at 2014 when CSR were mase mandatory in India. This year two factual progresses are noticed in terms of – Governance and contribution of private sectors to.

For study and analysis further facts and data are presented further-

Edit with WPS Office

This article and paper examined the parameters of most and least spending of different sectors for CSR in summarized manner.

RESEARCH METHODOLOGY

This research paper is an explanatory in pattern which is primary based on secondary sources such as article, books and websites for its data consideration.

STUDY OF CSR AND INDUSTRIES IN INDIA

CSR is an ethical term of business or industries which is used to represent the upliftment or development of deprived section of society by sharing one's earning who is well capable of evolution of CSR are as old as business or trade system in India:-

- Philosopher era- some of philosopher like koutilya promoted ethics and principles involvement in business activity and at that period of industrial system were pushed towards religious, charity as key moving factor (KMF) for this philanthropic tendency.
- 19th century or social inclination era- During 19th century CSR became part of social inclination apart from industrial or business interest because at that duration temples, school's, higher education institution and infrastructure were at priority. In fact term CSR came in to use in 1970's only.
- 20th century or philanthropic vision- during 20thcenture Indian economy witnessed shifting the emphasize of giving or traditional charity towards business-social issues. As the concept of being in isolation is worthless than overall development of business along with parties related to business as well as social environment are much impact fully boomed during this era, which ultimately rebounded CSR with industries and business.
- Modern era- Now industries-business and CSR became complementary to each other and also CSR has become KMF(key moving factor) for measurement of industrial growth or development thereby entailing a strategic emphasis on community development through educational, research, cultural projects with a view to consider wide-scale stakeholders responsibility and societal obligations instead of only their profit.
- Some other KMF for CSR contribution by industries in india-

1. Reduced involvement of government in economy of industrialization.
2. Greater disclosure and transparency requirement by stakeholders.
3. Outlook of investors for the perceptional decision making.
4. Labor turnover as well labor competitive market edge urge.

ANALYSIS

India is being more emphasized and focused as well with its CSR spending. As per the survey by KPMG India at year ended march 2018 CSR stood up Rs. 7536.30 cr. and also analyzation of top listed company of different sectors of India.

In 2018 CSR spending industries were 47% higher than spended at 2014 when CSR were mase mandatory in India. This year two factual progresses are noticed in terms of – Governance and contribution of private sectors to.

For study and analysis further facts and data are presented further-

I. Industries CSR spending based on 2017-18 data as per survey-

Industries spending (cr.)	CSR	%
Energy		
BFSI(banking &finan.)	2465	38.52
IT	1353	21.14
Mining & metal	1100	17.19
Consumer product	647	10.11
Services	635	9.92
Chemical	152	2.37
Media &ent.	25	0.39
	22	0.34
Total	6399	

Source: quartz India by KMPG India survey

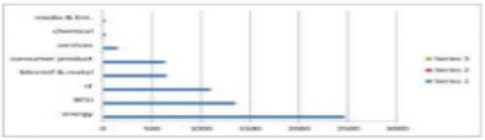

Graph 1.1

Energy and power sector leaded in terms of overall CSR % contribution in India which was followed by BFSI, IT, Mining .....etc. but overall contribution from media & entertainment. Amongst other were least being widespread industry and employing industries.

Edit with WPS Office

during this era, which ultimately rebounded CSR with industries and business.

- Modern era- Now industries-business and CSR became complementary to each other and also CSR has become KMF(key moving factor) for measurement of industrial growth or development thereby entailing a strategic emphasis on community development through educational, research, cultural projects with a view to consider wide-scale stakeholders responsibility and societal obligations instead of only their profit.

- Some other KMF for CSR contribution by industries in india-

1. Reduced involvement of government in economy of industrialization.

2. Greater disclosure and transparency requirement by stakeholders.

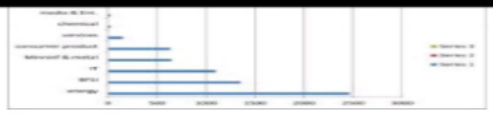

Graph 1.1

Energy and power sector leaded in terms of overall CSR % contribution in India which was followed by BFSI, IT, Mining .....etc. but overall contribution from media & entertainment. Amongst other were least being widespread industry and employing industries.

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XV, Issue No. 1, April-2018, ISSN 2230-7540

II. Application of CSR in Societal sectors (2017-2018)

Sectors	2017(cr.)	2018(cr.)	Changes
Education	2404	2202	-204
Health	1641	1691	50
Rural area	889	1029	140
Multiple area	826	505	-321
Environment	797	483	-314
Other area	187	625	438
Art & culture	168	279	111
Reducing inequality	136	325	189
War veteran	31	7	-24
Welfare fund	2	71	69
Technology in cult.	2	NIL	-2

Source: quartz India by KMPG India survey.

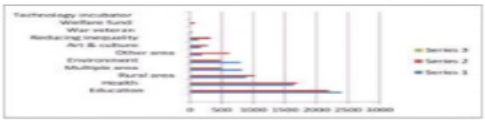

Graph 1.2

Spending of CSR fund is heavily skewed towards Education and Health for the year and maximum projects took up by sectors (60% approx...) was in this fields.

Which are then followed by rural development, environment, art and culture. Projects but somehow least projects were entertained in technological incubators field.

CONCLUSION

By above analysis it seems as maximum contribution is from energy and power thereby spending maximum at education and health section. As stated in 2014-18 CSR contribution are at higher change rate of 46% but then also seems to be sharp decline in number of projects implemented as per contribution percentage. Even the some of the area have not got the spending fund of CSR in 2018 such as technological incubators section and the least contribution from media and entertainment sector is also noted which are told to be bigger revenue contributory sector of the nation.

Average spending should be promoted for overall industrial sectors whether they fulfill the criterion or not. Particular minimum percentage contribution criterion should be devised for the big players who drop out from the CSR rule 2014 after being contributory of CSR. Corporate Governance ethics should be controlled for CSR spending actualization with own system or with implementing partners and annually application percentage should be prescribed.

REFERENCES

1. P. Harshavadhini and M. Kannappan (2017-18)-"Introspection of CSR in India".

2. Suneeratondon- "Indian Industries Spend Most and Least On Social Welfare"

3. https://qz.com>india>how indiancompanyspendoncsr.in

4. Hortensia Gorski, Mircea Fuciu, Natalia Croitor "Research on Corporate Social Responsibility in the Development Region Centre in Romania"

5. Bichta, C. (2003) Corporate social responsibility a role in government policy and regulation?, Research Report 16, Centre for the study of Regulated Industries (CRI). Available at http://www.bath.ac.uk/management/cri/pub pdf/Research_Reports/16_Bichta.pdf.

6. CII (2013). Handbook of corporate social responsibility. Cofideration of Indian industries, 2013, p.60.

7. CRISIL (2018). A survey report of CSR retrieved from, www.crisil .com

8. Hussain Sharafat (2014). Corporate social responsibility: initiative and its impacts on socio-economics development of rural areas in India. Asian journal of multidisciplinary studies. Vol.2(4), pp. 102-107.

Corresponding Author

Dr. Aradhana Shukla*

Assistant Professor, Vipra Mahavidyalaya, Raipur (CG)

saivibhuti1301@gmail.com

Edit with WPS Office

Volume I, Issue XVIII
October To December 2019

ISSN 2391-3807
E-ISSN 2394-3513
Impact Factor - 5.190

Divya Shodh Samiksha

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

दिव्य शोध समीक्षा

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email :** dssresearchjournal@gmail.com, **Website :** www.dssresearchjournal.com

Edit with WPS Office

Skill-Development Programme & Self-Employment Opportunity In Chhattisgarh

Mrs. Nidhi Shri Shukla Dr. Aradhna Shukla*

Abstract - Chhattisgarh has gradually evolved as a knowledge-based economy due to the abundance of capable and qualified human capital. With the constantly rising influence of resources, Chhattisgarh has immense opportunities to establish its distinctive position in the India. However, there is a need to further develop and empower the human capital to ensure the chhattisgarh's national competiveness. Despite the stress laid on education and training in this country, there is still a shortage of skilled manpower to address the mounting needs and demands of the economy.
Keywords - Skill-development and self-employment opportunity in chhattisgarh.

Introduction - The focus is to skill the youths in such a way so that they get employment and also improve self-employment. Provides training, support and guidance for all occupations that were of traditional type like carpenters, cobblers, welders, blacksmiths, masons, nurses, tailors, weavers etc. More emphasis will be given on new areas like real estate, construction, transportation, textile, gem industry, jewellery designing, banking, tourism and various other sectors, where skill development is inadequate or nil.

Objectives :

1. Key sectors for focus for skill development for better employment & livelihood(self-employment) in state.
2. Major livelihood sectors & key growth sector of state.
3. Level of skill required to met the demand of economic stability.

Hypothesis

1. There are sectors on whichchhattisgarh govt. has to focus on skill development for better employment & livelihood(self-employment) in state on the basis of required man-power.
2. Study proven data that has major livelihood sectors & key growth sector in state for human resource.

Research Methodology - This research study is based on secondary data obtained from Chhattisgarh planning commission for development.

Research Analysis - Our topic is " **Skill-develepment and self-employment opportunity in chhatisgarh.**" for which data related to key sectors, required human resources are taken from planning commission(CSSD) of C.G. Analysis is done with the help of or on the basis of available data through tables which are as follows:-

HR Requirement By 2015 Based On Cii Survey:-

Key Sector	Major Livel ihood Sectors	Skill Level	HR Required
Power	Agriculture/food processing	Minimum education skill	6.50lac
Mining/ minerals	Forest/forest produced based industry	ITI & diploma certification	5lac
Steel/ cement	Rural industry sector	Graduates	4.10lac
Construction	-	Specialized skill	0.64lac
Service Sector	-	-	-
Education	-	-	-
		TOTAL	16.40lac

HR Requirement Based On Mou's Signed With Upcoming Industries

Category	Mining	Power	Sponge/ Iron/ Cement	Total
Managerial	450	10000	7750	18200
Supervisory	2200	25000	12250	39450
Skilled	8350	40000	22600	70950
Unskilled	4400	10000	35000	49400
In-direct	-	200000	-	200000
TOTAL	15400	285000	77600	378000

By the above table major key sectors are 6 ,major self-employment sectors are 3 and the skill level sector wise gives enlarge view of requirement of man-power which is markably possible by the skill-development & self-employment programme of the state.

Conclusion - Thereby analysis and research studythe key sectors and major self-employment area's are of great impact on required human resources which ultimately hits the skill development programme and self-employment

*Asst. Professor (Commerce) Vipra Arts, Commerce and Physical Education College, Raipur (C.G) INDIA
**Asst. Professor (Commerce) Vipra Arts, Commerce and Physical Education College, Raipur (C.G) INDIA

opportunity in Chhattisgarh which finally lead the subject matter as well as the structure of different C.G. skill development and self-employment programme released by the C.M. of Chhattisgarh which under the flagship of 9 departments which undertakes 26 skill-development& self-employment programme in the 22 sectors of Chhattisgarh.

References :-

1. HR REQUIREMENT BY 2015 BASED ON CII SURVEY-C.G. Govt. booklet.
2. RURAL SKILL DEVELOPMENT: ISSUES AND CHALLENGES IN CHHATTISGARH-Rashmi Dewangan (Asst. prof. ,Shankracharya Mahavidyalaya Bhilai).
3. SKILL DEVELOPMENT FOR SELF EMPLOYMENT-Glory Swarupa(Research Scholar) & Ravi Kumar Goyal (Guid & Principal ,School Of Enterpreneurship ,BSDU,Jaipur).
4. SKILL DEVELOPMENT, EMPLOYMENTABILITY AND ENTERPRENEURSHIP THROUGH MAKE IN INDIAA STUDY- Dr. Jagdish Prasad, Asst. Dir. At directrare of technical education & Dr. DGM Purohit, Prof.JNV university jodhpur,Rajasthan.
5. IMPROVISING SKILL DEVELOPMENT AND EMPLOYABILITY POTENTIAL THROUGH HIGHER EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION IN INDIA-Seema pandey, Prof. JECRC Jaipur Rajasthan.

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

Edit with WPS Office